संख्या-18/2016/349/26-3-2016-4(56)/1996 टी.सी.।

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 28 जनवरी, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3806-07/स0क0/शिक्षा-अ/लखनऊ/2015-16, दिनांक 27.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित रू0-98471.65 लाख (रू0-नौ अरब चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख पैसठ हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि केन्द्रांश की प्रत्याशा में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाये। धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/संबंधित नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/ डाकघर मे जमा न की जाय।

(2) यह योजना शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से केन्द्रांश प्राप्त की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि का समायोजन किया जायेगा तथा अपेक्षित केन्द्रान्श भारत सरकार से प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत धनराशि एवं चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोजन न किया जाये और धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रयोजित योजनायें-0103-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति(के.100/रा.0-के.)-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-18/2016/349(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5-राज्य योजना आयोग-1/2
6-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ।
7-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।